



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 8 अगस्त, 2005/17 भावण, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 8 जुलाई, 2006

संख्या पी सी एच-एच ए (4)-7/2005-12282-88. —क्योंकि विभाग में जिला कुल्लू के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन हेतु प्रस्तावनाएं विचाराधीन हैं ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 2 के खण्ड (46) तथा धारा 3 की उप-धाराओं (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कुल्लू के निम्न अनुसूचि-1 में वर्णित राजस्व ग्रामों के उन भागों को जो अनुसूचि-1 के कोष्ठ संख्या-6 में अंकित है के लिए कोष्ठ संख्या-5 में अंकित नाम से ग्राम घोषित करने तथा निम्न अनुसूचि-2 में दिए गए विवरण अनुसार ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित/पुनर्गठित करने एवं नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा-4 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु ग्राम सभाओं के गठन करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करने और जिला कुल्लू के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों एवं आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश देते हैं ;

यदि निम्न अनुसूचि-1 तथा 2 में वर्णित ग्रामों की घोषणा तथा ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने हो तो वह अपने आक्षेप या

सुझाव इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला कुल्लू को प्रस्तुत कर सकेगा। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात, आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हो, ग्रहण नहीं किए जाएंगे।

राज्य सरकार, जिला कुल्लू के निम्न अनुसूचि-1 तथा 2 में वर्णित ग्रामों की घोषणा, ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नए ग्राम सभा क्षेत्रों के गठन बारे अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त, जिला कुल्लू की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूचि-1

1. विकास खण्ड कुल्लू :

क्रम सं०	ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम जिनके विभाजन से नए ग्रामों की घोषणा की जानी है	कोष्ठ संख्या-3 में वर्णित ग्राम के कुल खसरा नम्बर	कोष्ठ संख्या 3 में वर्णित ग्राम के विभाजन पर इस घोषणा आदेश द्वारा रखे गए नए नाम	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित नवघोषित ग्रामों में सम्मिलित होने वाले खसरा नम्बर
1	2	3	4	5	6
1.	ब्रनंगी	1. बाशिग	3804 से 4393	1. बाशिग	3804 से 4393
		2. कंगती	3521 से 3803	2. कंगती	3521 से 3803
		3. सराली वेहाड़।	3110 से 3520		
		4. कटाहर	2954 से 3109		
		5. बनोगी	1689 से 2953		
		6. नलहाच	801 से 1259		
		7. टिरंग	377 से 800		
		8. माचिछग	1260 से 1688		
		9. बवेली	1 से 376		
				1. नलहाच	801 से 1259
				2. टिरंग	377 से 800
				3. माचिछग	1260 से 1688
				4. बवेली	1 से 376

अनुसूचि-2

2. विकास खण्ड कुल्लू :

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा तथा इसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के वर्तमान तथा अनुसूची-1 के अन्तर्गत घोषित ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित होने वाले ग्रामों के नाम	अपवर्जित ग्रामों के लिए नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या-5 में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	वनोगी (वनोगी) ।	1. बाशिग 2. कंगती 3. सराली बेहाड़ 4. कटाहर 5. वनोगी 6. नलहाच 7. टिरंग 8. माच्छिंग 9. बवेली	1. बाशिग 2. कंगती	1. बाशिग (बाशिग) ।	कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम	कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्रामों को छोड़ कर, कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम वर्तमान ग्राम सभा 'वनोगी' में रहेंगे और वर्तमान ग्राम सभा का मुख्यालय 'वनोगी' में निर्धारित किया जाता है ।
		1. नलहाच 2. टिरंग 3. माच्छिंग 4. बवेली		2. नलहाच (बवेली)	कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम ।	कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्रामों को छोड़ कर कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम वर्तमान ग्राम सभा 'वनोगी' में रहेंगे ।

आदेश

शिमला-2, 13 जुलाई, 2005

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (5) 11/86-12485-91.—यह कि जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा श्री मातवर सिंह राणा को प्रधान, ग्राम पंचायत दगोह, विकास खण्ड लम्बागांव, जिला कांगड़ा, हि० प्र० के पद से पंचायत निधि की धनराशि के दुरुपयोग में संलिप्त होने के आरोप में उनके कार्यालय आदेश संख्या पंच०-के० जी० आर० ई० (15) 8/91-4912-17, दिनांक 15-7-2003 द्वारा निलम्बित किया गया था ।

यह कि मामले में वास्तविकता जानने हेतु नियमित जांच हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत उप-मण्डलाधिकारी (ना०), जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि० प्र० को विभाग के आदेश संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (5) 11/86-11876-882, दिनांक 25-8-2003 को सौंपी गई थी।

यह कि जांच अधिकारी द्वारा की गई विस्तृत जांच रिपोर्ट निदेशालय में प्राप्त हुई तथा जांच रिपोर्ट में दर्शाए गए तथ्यों का बारीकी से अध्ययन करने उपरान्त जो आरोप उनके विरुद्ध सिद्ध पाये गये उनका विवरण निम्न है :—

क्र० सं०	निर्माण कार्य का नाम	व्यय राशि	मूल्यांकन राशि	दुरनियोजन की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	निर्माण रास्ता काहण	13894/-	2754/-	11140/-
2.	निर्माण रास्ता गढियाड	9856/-	9039/-	817/-
3.	निर्माण रास्ता रैनगैल्टर से मिशन चन्द के घर तक।	15075/-	4673/-	10402/-
4.	निर्माण कच्चा रास्ता पुनी चण्ड के घर से भुलान तक।	9125/-	987/-	8138/-
5.	निर्माण रास्ता दगोह गठा से जमशानघाट तक।	12957/-	373/-	12584/-
कुल ..		60907/-	17,826/-	43,081/-

अतः उपरोक्त कार्यों पर कुल रु० 60,907/- रु० की राशि व्यय दर्शाई गई है, जबकि रिपोर्टों के अनुसार रु० 17,826/- रु० व्यय बनता है। इस प्रकार श्री मातवर सिंह राणा, प्रधान (नि०), ग्राम पंचायत, दगोह द्वारा रु० 43,081/- रु० की पंचायत निधि राशि का दुरनियोजन (Misappropriation) किया गया है।

अतः यह कि जांच रिपोर्ट पर विचार करने उपरान्त श्री मातवर सिंह राणा, प्रधान ग्राम पंचायत दगोह द्वारा वर्ती गई विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं तथा अपने कर्तव्य निर्वहन में आपत्तिजनक कार्य क्लाप के फलस्वरूप इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 15-10-2004 के अन्तर्गत उन्हें निष्कासनार्थ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यों न उन्हें उपरोक्त कृत्यों के लिए प्रधान पद से निष्कासित किया जाये तथा 15 दिनों के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर प्रदान किया गया।

अतः यह कि श्री मातवर सिंह राणा, प्रधान ग्राम पंचायत दगोह द्वारा प्रस्तुत उक्त कारण बताओ नोटिस के उत्तर से सरकार सन्तुष्ट नहीं हुई, क्योंकि उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है। जिसके फलस्वरूप श्री मातवर सिंह राणा, प्रधान ग्राम पंचायत, दगोह को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) के अन्तर्गत विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं तथा अपने कर्तव्य निर्वहन में आपत्तिजनक कार्य क्लाप के फलस्वरूप दोषी पाये जाने के कारण उन्हें प्रधान पद से हटाया जाना उचित है।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अधीन जो उन्हें हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त है का प्रयोग करने हुए श्री मानवर सिंह राणा, प्रधान, ग्राम पंचायत, दगोह, विकास खण्ड, लम्बागाँव, जिला कांगड़ा को उक्त कृत्य के लिए प्रधान पद से तुरन्त निष्काशित किया जाता है तथा छः वर्ष की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 146 (2) के अन्तर्गत पंचायत पदाधिकारी के रूप में निर्वाचन के लिए निरहित किया जाता है।

अधिसूचना

शिमला-171 009, 19 जुलाई, 2005

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (3)-8/94-II-12-746-51.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 मई, 2005 के अन्तर्गत जिला शिमला, विकास खण्ड मशोवरा, हिमाचल प्रदेश की ग्राम सभा 'चनोग' के मुख्यवास को स्थान 'सायरी' में बदल कर 'पवाबो' घोषित किए जाने वाले ग्राम सभा चनोग के सभा सदस्यों से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे और जिला शिमला के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझाव एवं आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

विभाग की उपरोक्त प्रस्तावना पर प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों को सुनने/निपटाने के पश्चात् उपायुक्त, जिला शिमला ने सिफारिश की है कि ग्राम सभा 'चनोग' के मुख्यवास को स्थान 'सायरी' से बदलकर स्थान 'पवाबो' में घोषित किया जाए।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अधीन जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 3 (2) (ग) के अन्तर्गत प्राप्त है, जिला शिमला के विकास खण्ड मशोवरा की ग्राम सभा 'चनोग' के मुख्यावास को स्थान 'सायरी' से बदल कर स्थान 'पवाबो' में घोषित/निर्धारित किए जाने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

आदेश

शिमला-171009, 27 जुलाई, 2005

संख्य पी0सी0एच0-एच0ए0 (5) 25/2005-13759-65.—यह कि श्री राजीव कुमार, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत पटनौण द्वारा दिनांक 8-2-2005 को खण्ड विकास अधिकारी, बमसन के माध्यम से अपना त्याग-पत्र जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर को इस आशय सहित प्रेषित किया कि प्रधान, ग्राम पंचायत पटनौण द्वारा अपनी मनमानी की जा रही है तथा ग्राम पंचायत के कार्य-क्लापों के निष्पादन में उन्हें विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। इस प्रकार प्रधान के तानाशाही व्यवहार तथा गलत नीतियों से तंग आकर वह अपना त्याग-पत्र दे रहे हैं;

यह कि श्री राजीव कुमार द्वारा प्रधान, ग्राम पंचायत पटनौण पर लगाए गए आरोपों की वास्तविकता जानने हेतु मामले में जांच खण्ड विकास अधिकारी, बमसन से करवाई गई तो शिकायत आधारहीन व निराधार पाई गई तथा जांच के दौरान श्री राजीव कुमार ने ब्यान किया है कि उन्होंने उप-प्रधान पद से त्याग-पत्र मानसिक दबाव के कारण दिया था जो कि गलत है जिसे वह वापिस लेना चाहते हैं तथा त्याग-पत्र में जो कुछ लिखा है वह गलत है;

यह कि श्री राजीव कुमार द्वारा प्रधान, ग्राम पंचायत पटनौण के विरुद्ध मिथ्या आरोप लगाकर न केवल प्रधान पद की गरिमा को ठेस पहुँचाई है अपितु एक जिम्मेदार पंचायत पदाधिकारी के आचरण के विरुद्ध कार्य किया है। जिसके दृष्टिगत उनका यह कृत्य हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा

146(1)(ख) की परिधि में आता है तथा उपरोक्त कृत्यों के लिए वह अवचार के दोषी पाए गए हैं जिसके फलस्वरूप उन्हें सरकार द्वारा दिनांक 2-6-2005 को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत उप-प्रधान पद से निष्कासित करने से पूर्व निष्कासनार्थ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यों न उन्हें उप-प्रधान पद से निष्कासित किया जाए तथा एक पक्ष के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर प्रदान किया गया ;

अतः यह कि श्री राजीव कुमार, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत पटनौण द्वारा प्रस्तुत उक्त कारण बताओ नोटिस के उत्तर से सरकार सन्तुष्ट नहीं हुई है, क्योंकि उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है। जिसके फलस्वरूप श्री राजीव कुमार, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत पटनौण को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) के अन्तर्गत अवचार के दोषी पाए जाने के कारण उन्हें उप-प्रधान पद से हटाया जाना उचित है।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अधीन जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) के अन्तर्गत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुए श्री राजीव कुमार, उप-प्रधान ग्राम पंचायत पटनौण, विकास खण्ड वमसन, जिला हमीरपुर को उक्त कृत्य के लिए उप-प्रधान पद से तुरन्त निष्कासित किया जाता है तथा छः वर्ष की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 146(2) के अन्तर्गत पंचायत पदाधिकारी के रूप में निर्वाचन के लिए निरहित किया जाता है।

शिमला-171 009, 2 अगस्त, 2005

संख्या पी0सी0 एच0एच0ए0 (5)44/2001-14106-12. - यह कि उपायुक्त, चम्बा द्वारा श्री माधो राम को प्रधान, ग्राम पंचायत जिल्लाघाट, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के पद से सरकारी धनराशि के दुरुपयोग, वित्तीय अनियमितताओं तथा अपने कर्तव्य निर्वहन में आपत्तिजनक कार्य क्लाप के फलस्वरूप उनके कार्यालय आदेश सं0 505-12, दिनांक 30-6-2004 द्वारा निलम्बित किया गया था ;

यह कि उपायुक्त, चम्बा द्वारा मामले की वास्तविकता जानने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) के अन्तर्गत उप-मण्डलाधिकारी (ना0), चम्बा, जिला चम्बा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया ;

यह कि जांच अधिकारी द्वारा की गई विस्तृत जांच रिपोर्ट उपायुक्त, चम्बा के माध्यम से दिनांक 4-2-2005 को निदेशालय में प्राप्त हुई तथा प्राप्त जांच रिपोर्ट में दर्शाये गये तथ्यों का बारीकी से अध्ययन करने उपरान्त जो आरोप श्री माधो राम, प्रधान के विरुद्ध सिद्ध पाए गए उनका विवरण निम्न है :-

1. प्रधान द्वारा सरकारी भूमि पर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना तथा पंचायत के नाम भूमि हस्तांतरण किए बिना सराए गैस्ट हाऊस तथा दो दुकानों का निर्माण किया गया है जबकि उक्त निर्माण कार्य पंचायत के नाम भूमि हस्तांतरण उपरान्त किया जाना चाहिए था।
2. गैस्ट हाऊस, चार दुकानों व दो स्टोरो के निर्माण पर निर्माण सामग्री का व्यय अधिक किया गया है। सहायक अभियन्ता (विकास), ग्रामीण विकास अधिकरण चम्बा द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसार चार दुकानों व दो स्टोरो के निर्माण में निर्माण सामग्री मु0 33,812/- रु0 तथा गैस्ट हाऊस के निर्माण में मु0 11,308/- रु0 की राशि के निर्माण सामग्री का व्यय किया गया है। इस प्रकार प्रधान से मु0 45,120/- रु0 की वसूली की जानी है।
3. गांव तरौली में बक्की का निर्माण स्वीकृत स्थान पर न करके प्रधान द्वारा अपनी मर्जी से अन्य स्थान पर किया गया है।

4. प्राथमिक पाठशाला श्रौयल के निर्माण का कार्य ठेके पर देकर मु० 55,760/- रु० व्यय किया गया तथा स्कूल का निर्माण गांव केहल की वजहसे गांव केहल और श्रौयल के मध्य में शिक्षा विभाग की अनुमति के बिना किया गया है। 11/2001 को स्कूल का कार्य शुरू किया गया तथा फरवरी, 2002 को नींव तक निर्माण कार्य करके कार्य बन्द कर दिया गया है। जांच अधिकारी द्वारा जांच के दौरान इस बारे में प्रधान से पूछने पर प्रधान ने बताया कि उप-निदेशक, प्राथमिक शिक्षा चम्बा के आदेशानुसार कार्य बन्द कर दिया गया था। परन्तु शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश की प्रति प्रधान प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। बिल अनुसार 60 बैंग सीमेंट इस निर्माण कार्य हेतु क्रय किया गया दर्शाया गया है परन्तु बिल में क्रय दिनांक नहीं दर्शाया गया है। इन प्रकार प्रधान द्वारा स्कूल का निर्माण निर्धारित अवधि के भीतर न करके राशि का दुरुपयोग किया है।

5. प्रधान द्वारा निम्न अवधि में निम्न राशि अनाधिकृत रूप से अपने पास रख कर राशि का दुरुपयोग किया है :—

राशि	अवधि	कुल दिन
मु० 90/1/-	5 मास 8 दिन	158 दिन
मु० 3783/-	18-9-2003 से 12-1-2004	117 दिन
मु० 12,731.40	31-10-2001 से 26-12-2001	57 दिन
मु० 22,280	1-3-2001 से 10-4-2001 तक	41 दिन
मु० 19,883	27-4-2001 से 2-6-2001 तक	37 दिन
मु० 34,418	16-6-2001 से 19-7-2001 तक	34 दिन

उपरोक्त अवधि में प्रधान द्वारा अनाधिकृत रूप से अपने पास रखी गई राशि पर 12.5 प्रतिशत ब्याज की दर से मु० 1854.54 की वसूली प्रधान से की जानी है।

अतः यह कि जांच रिपोर्ट पर विचार करने उपरान्त श्री माधो राम, प्रधान, ग्राम पंचायत शिल्लाघाट, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा द्वारा बर्ती गई विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं तथा अपने कर्तव्य निर्वहन में आपत्तिजनक कार्य क्लाप के फलस्वरूप इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 25-6-2005 के अन्तर्गत उन्हें निष्कासनार्थ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यों न उन्हें उपरोक्त कृत्यों के लिये प्रधान पद से निष्कासित किया जाये तथा 15 दिनों के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर प्रदान किया गया।

अतः यह कि श्री माधो राम, प्रधान, ग्राम पंचायत शिल्लाघाट द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर दिनांक 16-7-2005 को इस कार्यालय को प्रस्तुत किया। श्री माधो राम द्वारा प्रस्तुत उक्त कारण बताओ नोटिस के उत्तर से सरकार सन्तुष्ट नहीं हुई है, क्योंकि उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है। जिसके दृष्टिगत श्री माधो राम, प्रधान, ग्राम पंचायत शिल्लाघाट को विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं तथा अपने कर्तव्य निर्वहन में आपत्तिजनक कार्य क्लाप के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) के अन्तर्गत दोषी पाये गये हैं।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अधीन जो उन्हें हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए, श्री माधो राम, प्रधान, ग्राम पंचायत शिल्लाघाट, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा को उक्त कृत्य के लिये प्रधान पद से तुरन्त निष्कासित किया जाता है तथा छ. वर्ष की कालावधि के लिये उक्त अधिनियम की धारा 146 (2) के अन्तर्गत पंचायत पदाधिकारी के रूप में निर्वाचन के लिये निरहित किया जाता है।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव।

That, the entitlement of private ward/semi private ward to the Himachal Pradesh Government pensioners and their spouses will be the same as were being enjoyed by them for entitlement of special wards immediately before their retirement.

The reimbursement of room rent as indoor patient will be restricted to the rates applicable in Zonal Hospital Deen Dayal Upadhyay Hospital/IGMC, Shimla.

The reimbursement of medicines and other medical facilities will be governed by C. C. S. (MA) Rules, 1944 and instructions issued by the Government to this effect from time to time.

These orders shall take effect from the date of issue of this office memorandum and shall be valid for a period of one year.

This issues with the prior approval of the Finance Department (Regulations) obtained vide their U. O. No Fin. @ (3)-6/2004 dated 5-5-2005.

By order,

HARINDER HIRA,
Principal Secretary.